

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सख्या : 1166
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

मिड-डे मील तैयार करने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल

1166. श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी:
श्री नतुजी हालाजी ठाकोर:
श्री कांजीभाई पटेल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मिड-डे मील तैयार करने के अधिकांश केन्द्रों पर खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है;
- (ख) क्या सरकार सभी केन्द्रों पर एलपीजी का इस्तेमाल करने में राज्य सरकारों की सहायता करने का विचार रखती है;
- (ग) क्या सरकार उपयुक्त आकार के एलपीजी चूल्हे/स्टोव खरीदने के लिए अलग से निधियां मुहैया कराने और एलपीजी के नियमित इस्तेमाल पर आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) क्या सरकार एलपीजी सिलेण्डरों और रेगुलेटरों के लिए प्रतिभूति जमाराशि वहन करने में राज्य सरकारों की सहायता करने या विकल्पतः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को तेल कंपनियों को मिड-डे मील केन्द्रों से यह राशि वसूल न करने का निर्देश देने के लिए कहने का विचार रखती है?

उत्तर

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ० डी. पुरंदेश्वरी)**

(क): जी, हां।

(ख): कुकिंग उपस्करों (स्टोव, चूल्हा आदि), खाद्यान्नों और अन्य सामग्रियों के भंडारण हेतु कंटेनर और भोजन पकाने तथा परोसने के लिए बर्तनों के प्रावधान हेतु प्रति स्कूल 5000 रूपए की दर से एककालिक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत स्कूलों में भोजन पकाने के लिए एलपीजी सिलेण्डरों को घरेलू दरों पर प्रदान किया जाता है। इन निधियों का उपयोग करते हुए देश में 22 प्रतिशत स्कूल अभी एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।